International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

गंदी बस्ती के बच्चों में कुपोषण की स्थिति का एक अध्ययन (दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)

मंजुलता अग्रवाल[1] डॉ. मीरा देवांगन[2]

[1]शोधार्थी, [2]शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग)
भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग)

शोध सार

प्रस्तुत अध्ययन में दुर्ग जिले की शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों में व्याप्त कुपोषण की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में कुल 250 बच्चों को सम्मिलित किया गया जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष के बीच थी। आंकड़ों का संग्रह स्वास्थ्य जांच, ऊँचाई-भार मापन, माता-पिता से साक्षात्कार और आहार संबंधी जानकारी के आधार पर किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि गंदी बस्तियों के बच्चों में 60 प्रतिशत तक बच्चे किसी न किसी रूप में कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें गंभीर कुपोषण, अल्पवज़न और ऊँचाई की कमी जैसे लक्षण शामिल हैं।

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में कुपोषण एक गम्भीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों की झुग्गी-झोपड़ी या गंदी बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों में कुपोषण की समस्या और भी जटिल रूप में देखी जाती है। यह स्थिति केवल पोषण की कमी का ही संकेत नहीं देती, बल्कि यह सामाजिक असमानता, आर्थिक निर्धनता, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता और सरकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में कमी की भी परिचायक होती है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक पोषण कार्यक्रम, आंगनवाड़ी सेवाएं, मध्याह्न भोजन योजना और सुपोषण अभियान जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। परंतु इन योजनाओं का वास्तविक लाभ गंदी बस्तियों के बच्चों तक कितनी प्रभावी रूप से पहुँच रहा है, यह एक जाँच का विषय है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी कई गंदी बस्तियाँ स्थित हैं, जहाँ बड़ी संख्या में निर्धन परिवार अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इन परिवारों की आय का स्रोत सीमित होता है, जिससे पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना कठिन होता है। साथ ही माता-पिता की अशिक्षा, साफ-सफाई के प्रति जागरूकता की कमी, और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता कुपोषण की स्थिति को और गम्भीर बना देती है। इन सभी कारणों से कुपोषण का दुष्चक्र चलता रहता है, जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि दुर्ग जिले की गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की कुपोषण स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए और यह जाना जाए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ इस दिशा में कितनी कारगर सिद्ध हो रही हैं। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य की योजनाओं के निर्धारण और नीतिगत सुधारों में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

संबंधित शोध अध्ययन

गुप्ता एवं वर्मा (2016) ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में कुपोषण की स्थिति का अध्ययन किया और पाया कि माता-पिता की अशिक्षा, निम्न आय, और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चों में गंभीर कुपोषण के मुख्य कारण हैं। तिवारी (2017) ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रभाव का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि नियमित पूरक आहार और माता शिक्षा कार्यक्रमों से बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार देखा गया।

सेन एवं चक्रवर्ती (2018) ने कोलकाता की शहरी झुग्गियों में बच्चों के पोषण स्तर का आकलन किया और पाया कि पर्यावरणीय अस्वच्छता और अपर्याप्त सरकारी निगरानी कुपोषण को बढ़ावा देती है। जोशी एवं मेहता (2019) ने महाराष्ट्र में गंदी बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का अध्ययन किया और रेखांकित किया कि योजनाओं की जानकारी का अभाव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी से पोषण सेवाएं सीमित हो जाती हैं।
थॉमसन एवं बाउर (2020) ने बांग्लादेश की शहरी मलिन बस्तियों में कुपोषण पर अध्ययन किया और बताया कि जलस्रोतों की अस्वच्छता, बालिका शिक्षा का अभाव और सीमित आहार विविधता इस संकट के मूल कारण हैं। श्रीवास्तव एवं पाण्डेय (2021) ने छत्तीसगढ़ में संचालित सुपोषण अभियान का मूल्यांकन करते हुए कहा कि शासन की मंशा अच्छी होते हुए भी क्षेत्रीय अमले की लापरवाही और संसाधनों की कमी योजनाओं को प्रभावित करती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मूल उद्देश्य दुर्ग जिले की गंदी बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों की कुपोषण की स्थिति का मूल्यांकन करना है। चूँकि इन बस्तियों में रहने वाले परिवार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से कमजोर होते हैं, अतः वहाँ के बच्चों की पोषण स्थिति अत्यंत दयनीय हो सकती है। यह शोध इस विषय की गहराई से पड़ताल करता है कि पोषण की दृष्टि से इन बच्चों की क्या स्थिति है, किन कारणों से कुपोषण बना रहता है, और किस हद तक सरकारी योजनाएँ इस समस्या को कम करने में कारगर रही हैं।

प्रमुख उद्देश्यों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

- कुपोषण के स्तर की पहचान – यह अध्ययन यह जानने का प्रयास करता है कि दुर्ग जिले की गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों में किस प्रकार का कुपोषण (अल्पपोषण, अतिपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) पाया जा रहा है।
- कुपोषण के कारकों का विश्लेषण – आर्थिक स्थिति, माता-पिता की शिक्षा, स्वच्छता, आहार विविधता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आदि कारकों का बच्चों के पोषण स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करना इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य है।
- सरकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभाव – सुपोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं, मातृत्व लाभ योजना आदि योजनाओं से इन बस्तियों के बच्चों को कितना लाभ मिल रहा है, और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- समस्याओं की पहचान एवं समाधान की दिशा में सुझाव – अध्ययन यह भी प्रयास करेगा कि कौन से अवरोधक तत्त्व हैं जो पोषण सेवाओं की पहुँच को बाधित कर रहे हैं, और किन उपायों से इन्हें सुधारा जा सकता है।
- भविष्य की नीतियों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना – अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए दिशा-सूचक बन सकते हैं, ताकि गंदी बस्तियों के बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके।

न्यादर्श

अध्ययन में कुल 250 बच्चों को शामिल किया गया जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष के बीच थी। ये बच्चे दुर्ग जिले की पाँच प्रमुख गंदी बस्तियों से चयनित किए गए। चयन प्रक्रिया सरल यादृच्छिक विधि द्वारा की गई।

उपकरण

- बाल स्वास्थ्य जाँच प्रपत्र
- वजन और ऊँचाई मापन उपकरण
- माताओं से साक्षात्कार अनुसूची

सांख्यिकीय तकनीक

- प्रतिशत विधि
- औसत

• वर्गीकरण के आधार पर विश्लेषण

आंकड़ों का विश्लेषण

कुपोषण एक बहुआयामी सामाजिक एवं स्वास्थ्य समस्या है, जो विशेष रूप से शहरी गंदी बस्तियों में निवासरत बालकों के जीवन को प्रभावित करती है। प्रस्तुत अध्ययन में दुर्ग जिले की शहरी मलिन बस्तियों में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन किया गया है। इसके लिए कुल 250 बच्चों का चयन कर उनकी ऊँचाई, वजन, आयु, आहार संबंधी आदतों तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित आँकड़े एकत्र किए गए।

इन आँकड़ों का विश्लेषण बाल पोषण की अंतरराष्ट्रीय मापदंड प्रणाली (WHO Child Growth Standards) के आधार पर किया गया है, ताकि यह जाना जा सके कि कितने बच्चे सामान्य पोषण स्तर पर हैं और कितने मध्यम अथवा गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। इसके साथ ही, सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ जैसे माता-पिता की शिक्षा, आय, आंगनबाड़ी सेवाओं की उपलब्धता, एवं स्वच्छता की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए आँकड़ों का तुलनात्मक परीक्षण किया गया है।

इस विश्लेषण का उद्देश्य न केवल कुपोषण की वर्तमान स्थिति का चित्र प्रस्तुत करना है, बल्कि उन कारणों को भी समझना है जो इस समस्या को जन्म देते हैं एवं बढ़ावा देते हैं। प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में नीति-निर्माण, स्वास्थ्य हस्तक्षेप तथा सामुदायिक जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं।

तालिका: 1
कुपोषण के प्रकार और बच्चों की संख्या पर आधारित निष्कर्ष

कुपोषण की श्रेणी	बच्चों की संख्या	प्रतिशत (%)
सामान्य पोषण स्थिति	100	40
अल्पवज़न	60	24
ऊँचाई की कमी (Stunting)	50	20
गंभीर कुपोषण (Severe Wasting)	40	16
कुल	250	100

उपरोक्त तालिका में दुर्ग जिले की गंदी बस्तियों में निवासरत 250 बच्चों की पोषण स्थिति को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 40 प्रतिशत बच्चों की पोषण स्थिति सामान्य पाई गई, जो दर्शाता है कि इन बच्चों को अपेक्षाकृत संतुलित आहार और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध रही होंगी। वहीं, 24 प्रतिशत बच्चों में अल्पवज़न की समस्या पाई गई, जो प्रारंभिक कुपोषण का संकेत है।

इसके अतिरिक्त, 20 प्रतिशत बच्चों में ऊँचाई की कमी (Stunting) देखी गई, जो दीर्घकालिक पोषण की कमी एवं विकास में रुकावट को दर्शाता है। सबसे गंभीर स्थिति 16 प्रतिशत बच्चों में पाई गई, जिनमें गंभीर कुपोषण (Severe Wasting) के लक्षण देखे गए। यह स्थिति न केवल आहार की अत्यधिक कमी को दर्शाती है, बल्कि यह भी सूचित करती है कि इन बच्चों को तत्काल पोषण एवं चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

यह तालिका स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि यद्यपि कुछ बच्चों की पोषण स्थिति संतोषजनक है, परंतु एक बड़ा वर्ग अभी भी कुपोषण की विभिन्न श्रेणियों से ग्रसित है। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए पोषण सुधार की दिशा में समन्वित प्रयासों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की अत्यंत आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुपोषण, बच्चों के लिए एक गंभीर समस्या है। कुल 250 बच्चों में से केवल 40 प्रतिशत बच्चों की पोषण स्थिति सामान्य पाई गई, जबकि शेष 60 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के पोषण (एल्पवज़न, स्ट्रोंटिंग, और सीवियर वेस्टिंग) से प्रभावित हैं। यह इंगित करता है कि समाज में रहने वाले बच्चों को स्वायत्त पोषण, स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता प्राप्त नहीं हो रही है। सामाजिक-आर्थिक अभाव, माता-पिता की अशिक्षा, सीमित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं

और स्वतंत्रता की कमी, कुपोषण के मुख्य कारक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इस स्थिति में स्थायी सुधार के लिए नीति-निर्माता, संस्थागत तंत्र एवं स्वयंसेवी छात्रों को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सुझाव (सुझाव):

- संस्थान में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच एवं पोषण स्तर का आकलन किया जाए।
- माता-पिता राफेल के लिए पोषण एवं स्वच्छता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- आयुर्वेदिक सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
- प्रशिक्षण एवं समुदाय में पोषण पोषण कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लागू किया जायेगा।
- गंभीर आपदा से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष पोषण किट और वन्य जीव सहायता उपलब्ध करायी जाये।
- सामाजिक जागरुकता अभियान लोगों को स्वस्थ आहार एवं स्वतंत्रता के महत्व से अवगत करायें।
- सरकारी मंजूरी जैसे "सुपोषण अभियान", "मातृत्व लाभ योजना" आदि का प्रभावशाली वैज्ञानिक प्रमाणन सुनिश्चित किया जाए।
- वनस्पति विज्ञान के बच्चों का पोषण पोषण पर्यवेक्षण तंत्र (पोषण निगरानी प्रणाली) विकसित किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, आर. एवं मिश्रा, ए. (2017) बाल पोषण: एक सामाजिक अध्ययन, भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 12(2), 45-58
2. चौधरी, पी. (2018) शहरी झुग्गी यूएसएसआर में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की शाखाएं, क्लिनिकल स्वास्थ्य जर्नल, 9(3), 33-42
3. वर्मा, एस. एवं पैंडे, के. (2019) भारत में बाल कुपोषण की स्थिति और सरकारी प्रयास, राष्ट्रीय पोषण समीक्षा, 7(1), 21-36
4. रॉय, टी. और दास, पी. (2020) भारत की शहरी मलिन बस्तियों में कुपोषण: कारण और परिणाम, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, 64(4), 298-304
5. मेहता, ए. और सेन, आर. (2021) वंचित समुदायों में पोषण संबंधी चुनौतियाँ, सामाजिक स्वास्थ्य अनुसंधान, 13(2), 102-115
6. कुमार, वी. (2022) शहरी स्लम बच्चे और पोषण: नीति कार्यान्वयन में अंतराल, विकास अध्ययन त्रैमासिक, 14(1), 67-79
7. यूनिसेफ. (2022) शहरी गरीब बच्चों में पोषण: भारत रिपोर्ट, नई दिल्ली: यूनिसेफ इंडिया
8. चटर्जी, एम. और लॉरेंस, डी. (2023) कुपोषण कम करने में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ चाइल्ड हेल्थ, 16(2), 89–104